



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 210]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 25, 2019/चैत्र 4, 1941

No. 210]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 25, 2019/CHAITRA 4, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2019

सं. 14/2019-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 237(अ).—जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यूरोपीय संघ, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है), में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित “एसीटोन” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2914 11 00 के अंतर्गत आता है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 10/2014-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 11 मार्च, 2014, जिसे सा.का.नि. संख्या 178(अ), दिनांक 11 मार्च, 2014 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में अधिसूचना संख्या 7/26/2018-डीजीएडी, दिनांक 6 जुलाई, 2018, जिसे दिनांक 6 जुलाई, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के अनुपालन में समीक्षा शुरू की थी ;

और जहां कि उक्त विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 7/26/2018-डीजीएडी, दिनांक 5 मार्च, 2019, जिसे दिनांक 05 मार्च, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, , खंड 1, में प्रकाशित किया गया था, में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि ;

- (1) प्रश्नगत उत्पाद का विषयगत देशों से इसके सस्ते मूल्य पर आयात जारी है;
- (2) फालतू आयात के कारण घरेलू उद्योग को लगातार क्षति हुई है;
- (3) यदि विषयगत देशों से होने वाले आयातों पर प्रतिपाटन शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो इससे घरेलू उद्योग को लगातार क्षति होने की संभावना है;

- (4) रिकार्ड में प्राप्त सूचना से यह प्रकट होता है कि यदि लागू एडीडी को इस स्तर पर समाप्त कर दिया जाए तो इन उत्पादों की भरमार और इनसे होने वाली क्षति जारी रहेगी;
- (5) इस जांच अवधि के दौरान सिंगापुर के एक उत्पादक और निर्यातक ने सहयोग दिया है। मैसर्स मितसुई फिनोल सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड ने सामान्य मूल्य से कम पर निर्यात किया है और इस प्रकार होने वाले फालतू आयात से घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हो रही है;
- (6) वर्तमान समीक्षा जांच के दौरान यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी भी उत्पादक या निर्यातक ने सहयोग नहीं दिया है। प्राप्त डाटा से पता चलता है कि इन देशों से सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात हुआ है।

और उन्होंने घरेलू उद्योग को होने वाली इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत वस्तु जो कि विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित है और भारत में आयातित है, के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपादन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उनका आंकलन तथा उन पर प्रतिपादन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 और 23 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात्, एतद्वारा, उक्त विषयगत वस्तुओं पर जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन टैरिफ मद के अंतर्गत आती है जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित हैं और भारत में आयातित हैं, और कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि की बराबर की दर से और कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा और माप इकाई में प्रतिपादन शुल्क लगाती है, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मूलतः उत्पादक और/या निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क की राशि	इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	2914 11 00	एसीटोन	सिंगापुर	मैसर्स मितसुई फिनोल सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड	56.91	अमेरिकी डॉलर/मैट्रिक टन
2.			सिंगापुर	अन्य कोई भी	121.04	अमेरिकी डॉलर/मैट्रिक टन
3.			यूरोपीय संघ	कोई भी	277.85	अमेरिकी डॉलर/मैट्रिक टन
4.			दक्षिण अफ्रीका	कोई भी	179.65	अमेरिकी डॉलर/मैट्रिक टन
5.			संयुक्त राज्य अमेरिका	कोई भी	213.76	अमेरिकी डॉलर/मैट्रिक टन

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपादन शुल्क अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपादन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. 354/65/2007-टीआरयू (पार्ट-III)]

डॉ. श्रीपार्वती एस. एल., अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th March, 2019

No. 14/2019-Customs (ADD)

G.S.R. 237(E).—Whereas, the designated authority, *vide* notification No. 7/26/2018 DGAD, dated the 6th July, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 6th July, 2018, had initiated the review in term of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of ‘Acetone’ (hereinafter referred to as the subject goods), falling under the tariff item 2914 11 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from European Union, Singapore, South Africa and United States of America (hereinafter referred to as the subject countries), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 10/2014-Customs (ADD), dated the 11th March, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 178 (E), dated the 11th March, 2014;

And whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, the Designated Authority in its final findings, published *vide* notification No.7/26/2018-DGAD, dated the 5th March, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 5th March, 2019, has come to the conclusion that-

- (1) The product under consideration continues to be imported at the dumped prices from the subject countries;
- (2) The domestic industry has suffered continued injury on account of dumped imports;
- (3) The continued injury to the domestic industry in on account of dumped imports and is likely to continue if the anti-dumping duties from subject countries are ceased;
- (4) The information on record clearly shows likelihood of continuation of dumping and injury in case the ADD in force is allowed to cease at this stage;
- (5) One producer exporter has cooperated from Singapore during the review investigation. M/s Mitsui Phenols Singapore Pte. Ltd has exported to India below the normal value and dumped imports are causing the material injury to the DI;
- (6) None of the producer’s exporters from European Union, South Africa and United States of America have co-operated in the present review investigation. The data available indicates that exports from these countries have been made at prices below the normal value;

And has recommended the imposition of definitive anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18, 20 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in or exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (4), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (5), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (6), in the currency and per unit of measurement specified in the corresponding entry in column (7) of the said Table.

TABLE

S. No.	Tariff Item	Description of Goods	Country of Origin and/or Export	Producer	Duty Amount	Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	2914 1100	Acetone	Singapore	M/s Mitsui Phenols Singapore Pte. Ltd	56.91	USD/MT
2.			Singapore	Any other	121.04	USD/MT
3.			European Union	Any	277.85	USD/MT
4.			South Africa	Any	179.65	USD/MT
5.			USA	Any	213.76	USD/MT

2. The anti-dumping duty imposed shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

[F. No. 354/65/2007–TRU (Pt. III)]

Dr. SREEPARVATHY S. L., Under Secy.